



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 4 अप्रैल, 2007/14 चैत्र, 1929

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 4 अप्रैल, 2007

संख्या वि०स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-20/2007.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्राइवेट क्लिनिकल स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक-6) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2007 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाज़टा,  
सचिव।

# हिमाचल प्रदेश प्राइवेट क्लिनिकल स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2007

## खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम ।
2. परिभाषाएं ।
3. रजिस्ट्रीकरण ।
4. अनिवार्य शर्तें ।
5. वर्गीकरण ।
6. क्लिनिकल स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ।
7. राज्य रजिस्ट्रार ।
8. राज्य क्लिनिकल स्थापन परिषद् ।
9. राजस्व के स्रोत ।
10. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।
11. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण से पूर्व कोई जांच नहीं ।
12. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण ।
13. स्थायी रजिस्ट्रीकरण ।
14. स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।
15. रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण ।
16. रजिस्ट्रीकृत क्लिनिकल स्थापन का निरीक्षण ।
17. सन्देहयुक्त अरजिस्ट्रीकृत क्लिनिकल स्थापन का निरीक्षण ।
18. अपीलें ।
19. क्लिनिकल स्थापन का रजिस्टर ।
20. क्लिनिकल स्थापन के राज्य रजिस्टर का अनुरक्षण ।
21. रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित अपराध ।
22. आदेश की अवज्ञा, बाधा डालना और सूचना देने से इन्कार करना ।
23. लघु प्रकृति की कमियां ।
24. साधारण उपबन्ध ।
25. कम्पनियों द्वारा अपराध ।
26. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
27. अपराध का संज्ञान ।
28. विवरणियां देना ।
29. प्राधिकारी, आदि का लोक सेवक होना ।
30. नियम बनाने की शक्ति ।
31. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

**हिमाचल प्रदेश प्राइवेट क्लिनिकल स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2007**

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट क्लिनिकल स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट क्लिनिकल स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन हेतु व्यापक विधायी ढांचा अधिनियमित करना लोक हित में समीचीन समझा गया है ।

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मानकीकृत करने के दृष्टिगत उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 द्वारा यथाव्यादेशित (आदिष्ट) लोक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मानक विहित करना समीचीन समझा गया है ।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश क्लिनिकल स्थापन संक्षिप्त नाम। रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम, 2007 है ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

(क) "प्राधिकारी" से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रमाणपत्र" से धारा 10 की उपधारा (4) या धारा 14 की उपधारा (7) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(ग) "क्लिनिकल स्थापन" से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है अस्पताल, प्रसूति गृह, नर्सिंग होम, औषधालय, क्लिनिक, सेनिटोरियम या संस्थान चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो बीमारी, चोट (क्षति), अंगविकार,

## हिमाचल प्रदेश प्राइवेट क्लिनिकल स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2007

### खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम ।
2. परिभाषाएं ।
3. रजिस्ट्रीकरण ।
4. अनिवार्य शर्तें ।
5. वर्गीकरण ।
6. क्लिनिकल स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ।
7. राज्य रजिस्ट्रार ।
8. राज्य क्लिनिकल स्थापन परिषद् ।
9. राजस्व के स्रोत ।
10. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।
11. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण से पूर्व कोई जांच नहीं ।
12. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण ।
13. स्थायी रजिस्ट्रीकरण ।
14. स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।
15. रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण ।
16. रजिस्ट्रीकृत क्लिनिकल स्थापन का निरीक्षण ।
17. सन्देशयुक्त अरजिस्ट्रीकृत क्लिनिकल स्थापन का निरीक्षण ।
18. अपीलें ।
19. क्लिनिकल स्थापन का रजिस्टर ।
20. क्लिनिकल स्थापन के राज्य रजिस्टर का अनुरक्षण ।
21. रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित अपराध ।
22. आदेश की अवज्ञा, बाधा डालना और सूचना देने से इन्कार करना ।
23. लघु प्रकृति की कमियां ।
24. साधारण उपबन्ध ।
25. कम्पनियों द्वारा अपराध ।
26. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
27. अपराध का संज्ञान ।
28. विवरणियां देना ।
29. प्राधिकारी, आदि का लोक सेवक होना ।
30. नियम बनाने की शक्ति ।
31. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।



**हिमाचल प्रदेश प्राइवेट क्लिनिकल स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2007**

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट क्लिनिकल स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट क्लिनिकल स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन हेतु व्यापक विधायी ढांचा अधिनियमित करना लोक हित में समीचीन समझा गया है ।

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मानकीकृत करने के दृष्टिगत उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 द्वारा यथाव्यादेशित (आदिष्ट) लोक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मानक विहित करना समीचीन समझा गया है ।

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश क्लिनिकल स्थापन संक्षिप्त नाम। रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम, 2007 है ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

(क) "प्राधिकारी" से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रमाणपत्र" से धारा 10 की उपधारा (4) या धारा 14 की उपधारा (7) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(ग) "क्लिनिकल स्थापन" से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है अस्पताल, प्रसूति गृह, नर्सिंग होम, औषधालय, क्लिनिक, सेनिटोरियम या संस्थान चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो बीमारी, चोट (क्षति), अंगविकार,

असामान्यता या गर्भावस्था के लिए निदान, उपचार या देखभाल करने के लिए अपेक्षित बिस्तरों सहित या बिस्तरों से रहित सेवाएं, प्रसुविधाएं प्रदान करता है और इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित उक्त सेवाएं प्रदान करने वाली सुचल इकाई (मोबाइल युनिट) भी है, किन्तु राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित क्लिनिकल स्थापन इसके अन्तर्गत नहीं है ;

- (घ) "परिषद्" से इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन गठित राज्य क्लिनिकल स्थापन-परिषद् अभिप्रेत है ;
- (ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;
- (च) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;
- (छ) "व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो चिकित्सा (मैडिसन) की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति और उसकी समस्त शाखाओं के व्यवसाय (प्रेक्टिस) में लगा हुआ है तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम, द्वितीय या तृतीय अनुसूची में यथाविहित अर्हता रखता है;
- (ज) "चिकित्सा" (मैडिसन) का वही अर्थ होगा जो हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (च) में है ;
- (झ) "मानकों" से ऐसी शर्तें अभिप्रेत हैं जो इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन विहित की जाएं;
- (ञ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ;
- (ट) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;
- (ठ) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और

(ढ) "रजिस्टर" या "राज्य रजिस्टर" से इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर अभिप्रेत है तथा 'रजिस्ट्रीकृत' और 'रजिस्ट्रीकरण' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

3. (1) कोई भी व्यवसायी क्लिनिकल स्थापन को तब तक नहीं चलाएगा रजिस्ट्रीकरण । जब तक कि इसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत न किया गया हो ।

(2) किसी भी व्यक्ति को किसी क्लिनिकल स्थापन द्वारा तब तक नियोजित या सम्बद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी राज्य या केन्द्रीय अधिनियम के अधीन सुसंगत मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता न रखता हो ;

**स्पष्टीकरण.**—पद "चलाएगा" से क्लिनिकल स्थापन में उपचार, निदान, या परिचर्या की व्यवस्था करने के लिए रोगियों को स्वीकार करना अभिप्रेत है ।

4. प्रत्येक क्लिनिकल स्थापन रजिस्ट्रीकरण के लिए और तत्पश्चात ऐसी अनिवार्य शर्तें पूरी करेगा जैसी राज्य सरकार विहित करे, जिसके अन्तर्गत प्रसुविधाओं और शर्तें । सेवाओं के लिए मानक, कार्मिक अर्हताएं, अभिलेखों का अनुरक्षण और अनुषंग (इनसिडेन्ट) रिपोर्टिंग सम्मिलित हो सकेंगी ।

5. क्लिनिकल स्थापन ऐसे प्रवर्गों में वर्गीकृत किए जाएंगे, जैसे राज्य वर्गीकरण । सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं , और क्लिनिकल स्थापन के विभिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न मानक विहित किए जा सकेंगे ।

6. (1) जिला का उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त, जैसा राज्य सरकार क्लिनिकल स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी । द्वारा, प्रत्येक जिला के लिए अधिसूचित किया जाए, इस अधिनियम के अधीन, सुचल इकाइयों (मोबाइल युनिट) को अपवर्जित करके, अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर क्लिनिकल स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी होगा ।

(2) जिला का मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्लिनिकल स्थापनों का जिला रजिस्ट्रार होगा ।

(3) जिला रजिस्ट्रार का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी विवरणियां, जैसी क्लिनिकल स्थापनों के राज्य रजिस्टर के नियमित अद्यतन के लिए विहित की जाएं और ऐसी अन्य सूचना जैसी परिषद् द्वारा अपेक्षित हो, भेजे ।

राज्य  
रजिस्ट्रार।

7. (1) राज्य सरकार निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश को क्लिनिकल स्थापनों के राज्य रजिस्ट्रार के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) राज्य के भीतर और बाहर, किसी परिवहन प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत समस्त सुचल इकाइयां (मोबाइल युनिट) राज्य रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत की जाएंगी ।

(3) क्लिनिकल स्थापनों के राज्य रजिस्ट्रार का , क्लिनिकल स्थापनों के राज्य रजिस्टर को संकलित और अद्यतन करने का उत्तरदायित्व होगा और राज्य रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए डिजिटल फारमेट में मासिक विवरणियां भी भेजने का भी दायित्व होगा ।

राज्य  
क्लिनिकल  
स्थापन  
परिषद्।

8. (1) क्लिनिकल स्थापनों के लिए मानक अवधारित करने हेतु और निम्नलिखित के लिए, राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली राज्य क्लिनिकल स्थापन परिषद् होगी, -

- (क) क्लिनिकल स्थापन का वर्गीकरण करने के लिए ;
- (ख) न्यूनतम मानकों को विकसित और अवधारित करने और उनका समय-समय पर पुनर्विलोकन करने के लिए ;
- (ग) क्लिनिकल स्थापनों के राज्य रजिस्टर का संकलन करने, अनुरक्षण करने और उसे अद्यतन करने के लिए ;
- (घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए ।

(2) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात् :-

- |       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| (क)   | सचिव (स्वास्थ्य)<br>हिमाचल प्रदेश सरकार   | अध्यक्ष ;           |
| (ख)   | निदेशक, चिकित्सा<br>शिक्षा, हिमाचल प्रदेश   | पदेन सदस्य;         |
| (ग)   | निदेशक, स्वास्थ्य<br>सेवाएं, हिमाचल प्रदेश  | पदेन सदस्य;         |
| (घ)   | निदेशक, (भारतीय<br>चिकित्सा पद्धति)<br>(आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश   | पदेन सदस्य;         |
| (ङ)   | रजिस्ट्रार  |                     |
| (i)   | हिमाचल प्रदेश<br>चिकित्सा परिषद्;   | पदेन सदस्य          |
| (ii)  | हिमाचल प्रदेश<br>दन्त चिकित्सा<br>परिषद् ;  | पदेन सदस्य          |
| (iii) | हिमाचल प्रदेश<br>नर्सिंग परिषद्;  | पदेन सदस्य          |
| (iv)  | हिमाचल प्रदेश<br>सह-चिकित्सीय<br>परिषद्;  | पदेन सदस्य          |
| (v)   | हिमाचल प्रदेश<br>फार्मसी (भैषजिकी)<br>परिषद्;   | पदेन सदस्य          |
| (च)   | प्राइवेट अस्पताल के स्वामियों में से<br>एक प्रतिनिधि ;  | गैर सरकारी<br>सदस्य |
| (छ)   | राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए<br>जाने वाले, अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा<br>पद्धति, जिसका कोई वैधानिक नियामक<br>प्राधिकरण स्थापित नहीं किया गया है, के<br>तीन से अनधिक ख्याति प्राप्त प्रतिनिधि ; | गैर सरकारी<br>सदस्य |

(ज) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य स्तरीय उपभोक्ता समूहों या गैर सरकारी संगठनों में से, एक प्रतिनिधि । गैर सरकारी सदस्य

(3) परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्य, एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, परन्तु वे पुनः नामनिर्दिष्ट किए जाने के पात्र होंगे :

परन्तु नामनिर्दिष्ट सदस्य तब तक के लिए पद धारण करेगा जब तक वह उस पद पर, जिसके फलस्वरूप वह परिषद् के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया था, नियुक्त रहता है ।

(4) परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्य परिषद् की प्रभावी बैठक के लिए ऐसी दर पर यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के हकदार होंगे, जैसी विहित की जाए ।

(5) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यक्षीन, गणपूर्ति नियत करने सहित इसके द्वारा किए जाने वाले समस्त काम-काज के संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया विहित कर सकेगी ।

(6) परिषद्, उप-समितियां गठित कर सकेगी और ऐसी उप-समितियों के लिए, ऐसे व्यक्तियों को, जो परिषद् के सदस्य नहीं हैं, किसी विशिष्ट मामले के विचार के लिए, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अस्थायी आधार पर नियुक्त कर सकेगी ।

(7) परिषद्, इसमें किसी रिक्ति के होते हुए भी अपने कृत्यों का पालन कर सकेगी ।

(8) राज्य सरकार, किसी व्यक्ति को परिषद् का सचिव नियुक्त कर सकेगी और परिषद् के लिए ऐसे अन्य कर्मचारिवृन्द की व्यवस्था कर सकेगी, जैसी परिषद् आवश्यक समझे ।

(9) परिषद्, किसी व्यक्ति या निकाय को अपने साथ ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी विहित की जाएं, सहवद्ध कर सकेगी जिनकी सहायता या परामर्श इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिए इस द्वारा अपेक्षित हो ।

(10) परिषद्, मानकों के अवधारण के लिए और क्लिनिकल स्थापनों के वर्गीकरण के लिए विनियमों द्वारा विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार परामर्शक प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगी ।

9. परिषद्, राज्य रजिस्टर के अनुरक्षण के लिए, प्राधिकरण से ऐसी फीस राजस्व के प्रभारित कर सकेगी, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए : स्रोत ।

परन्तु ऐसी फीस क्लिनिकल स्थापन से, रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रभारित कुल फीस के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

10. (1) क्लिनिकल स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्ररूप में ऐसे व्यौरों और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, से अन्तर्विष्ट आवेदन के लिए प्राधिकारी को किया जाएगा । आवेदन ।

(2) प्राधिकारी आवेदनों का आन लाईन प्रस्तुत करना सुकर बनाएगा ताकि प्राधिकारी और आवेदन के मध्य अन्तराणीक (इन्टरफेस) कम किया जा सके ।

(3) कोई भी क्लिनिकल स्थापन, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान है , चाहे रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, इसके रजिस्ट्रीकरण के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर प्राधिकारी को आवेदन करेगा ।

(4) प्राधिकारी, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर , ऐसे प्ररूप में ऐसी विशिष्टियों और सूचना से अन्तर्विष्ट , जैसी विहित की जाए अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रदान किया गया अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक आधार पर नवीकृत किया जाएगा ।

(6) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, क्लिनिकल स्थापन में सहजदृश्य स्थान पर, ऐसी रीति में रखा जाएगा, ताकि ऐसे स्थापन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दृश्यमान हो ।

(7) प्रमाण-पत्र के गुम, नष्ट, विकृत या क्षतिग्रस्त होने की दशा में प्राधिकारी क्लिनिकल स्थापन के अनुरोध पर और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के संदाय पर, प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

(8) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनंतरणीय होगा और स्वामित्व के परिवर्तन या प्रबन्धन के परिवर्तन या क्लिनिकल स्थापन के रूप में कार्य करने से प्रवरित हो जाने की दशा में, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राधिकारी को अभ्यर्पित किया जाएगा तथा क्लिनिकल स्थापन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए पुनः आवेदन करेगा ।

अनन्तिम  
रजिस्ट्रीकरण  
से पूर्व कोई  
जांच नहीं ।

11. (1) अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से पूर्व प्राधिकारी द्वारा कोई भी जांच संचालित की जानी अपेक्षित नहीं होगी ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के अनन्तिम प्रमाणपत्र प्रदान करने पर भी, प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण के अनन्तिम प्रमाणपत्र को प्रदान करने से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तावित क्लिनिकल स्थापन की समस्त विशिष्टियां, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाएं, प्रकाशित करवाएगा ।

रजिस्ट्रीकरण  
का  
नवीकरण ।

12. (1) प्राधिकारी, उन क्लिनिकल स्थापनों, जिनका रजिस्ट्रीकरण आगामी पैंतालीस दिनों के भीतर समाप्त होने वाला है, के नामों को ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, प्रकाशित करवाएगा ।

(2) प्राधिकारी, प्रत्येक क्लिनिकल स्थापन को, रजिस्ट्रीकरण के अवसान से पैंतालीस दिन पूर्व, कम्प्यूटर जनित नोटिस या तो इलैक्ट्रोनिकली या डाक द्वारा भिजवाएगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन, अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता के अवसान से ठीक पूर्व किया जाएगा और यदि नवीकरण के लिए आवेदन अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान के पश्चात् किया गया है, तो प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण ऐसी विलम्ब फीस, जैसी विहित की जाए, के संदाय पर अनुज्ञात करेगा ।

स्थायी  
रजिस्ट्री-  
करण ।

13. (1) धारा 10 के अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, स्थायी रजिस्ट्रीकरण तभी प्रदान किया जाएगा जब राज्य सरकार ने परिषद् द्वारा यथा अवधारित, क्लिनिकल स्थापनों के लिए न्यूनतम मानक विहित कर दिए हों ।

(2) क्लिनिकल स्थापन, जिनकी बाबत न्यूनतम मानक विहित किए जा चुके हैं, को अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण, मानकों की अधिसूचना की तारीख से बारह मास की अवधि के परे (पश्चात्) प्रदान या नवीकृत नहीं किया जाएगा ।



14. (1) स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप स्थायी और ऐसी रीति में और अन्तर्विष्ट ऐसे ब्यौरे तथा ऐसी फीस के साथ जैसी विहित रजिस्ट्रीकरण के लिए की जाए, किया जाएगा। आवेदन।

(2) प्राधिकारी, स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पूर्व उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई समस्त सूचना/ब्यौरे जनसाधारण की सूचना के लिए, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, तीस दिन की अवधि के लिए प्रकाशित करवाएगा।

(3) जिला रजिस्ट्रार, विहित किए गए न्यूनतम मानकों की बाबत क्लिनिकल स्थापन का निरीक्षण करवाएगा और उसे सम्बद्ध प्राधिकारी को सम्प्रेषित करेगा।

(4) यदि प्राधिकारी द्वारा, प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है (होते हैं) या जिला रजिस्ट्रार की रिपोर्ट विहित न्यूनतम मानकों के बारे में संतोषजनक है, तो स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर दिया जाएगा।

(5) यदि कोई आक्षेप नियत अवधि के भीतर प्राप्त होता है (होते हैं) या जिला रजिस्ट्रार की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, तो इस प्रकार प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) आवेदक को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, परन्तु तीस दिन के अपश्चात्, संसूचित किए जाएंगे।

(6) नियत अवधि के अवसान के तुरन्त पश्चात् और तत्पश्चात् आगामी तीस दिन के भीतर प्राधिकारी, आदेश द्वारा, —

- (क) आवेदन को स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञात करेगा; या
- (ख) आवेदन को स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए अननुज्ञात (नामंजूर) करेगा।

(7) यदि आवेदन अनुज्ञात किया गया है तो प्राधिकारी, ऐसे प्ररूप में, और ऐसी विशिष्टियां जैसी विहित की जाए, स्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(8) यदि स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञात नहीं किया गया है तो प्राधिकारी इसके लिए कारणों का स्पष्टतः विवरण देगा :

परन्तु क्लिनिकल स्थापन को उन कमियों में सुधार के पश्चात् जिनको आधार मानकर पूर्वतर आवेदन अननुज्ञात किया गया था स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः आवेदन करने से, विवर्जित नहीं किया जाएगा चाहे, इसके पूर्वतर आवेदन को अननुज्ञात किया जा चुका हो।

रजिस्ट्रीकरण  
का प्रति-  
संहरण।

15. (1) क्लिनिकल स्थापन को रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् यदि किसी भी समय प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि, -

- (क) रजिस्ट्रीकरण की शर्तों की अनुपालना नहीं की जा रही है ; या
- (ख) कोई अन्य आधार जो प्राधिकारी को, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को नामंजूर करने के लिए अधिकृत करता, आवेदन करते समय छिपाया गया था ; या
- (ग) क्लिनिकल स्थापन के प्रबन्धन से न्यस्त व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जा चुका हो;

तो वह कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन नोटिस में वर्णित कारणों के आधार पर इसके रजिस्ट्रीकरण को क्यों न रद्द कर दिया जाए। क्लिनिकल स्थापन को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यदि प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का कोई भंग है, तो वह ऐसे क्लिनिकल स्थापन के विरुद्ध किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा, -

- (क) जहां ऐसे आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील के लिए विहित अवधि के अवसान पर तुरन्त कोई अपील नहीं की गई है ; या
- (ख) जहां अपील प्रस्तुत की गई है और उसे ऐसे आदेश के खारिज किए जाने की तारीख से खारिज कर दिया गया है :

परन्तु यदि रोगियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को आसन्न खतरा है तो प्राधिकारी कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के पश्चात् स्थापन को इसके किन्हीं कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए अवरुद्ध कर सकेगा।

रजिस्ट्रीकृत  
क्लिनिकल  
स्थापन का  
निरीक्षण।

16. (1) प्राधिकारी, या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी क्लिनिकल स्थापन, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्करों तथा क्लिनिकल स्थापन द्वारा संचालित और किए गए कार्य की बाबत भी निरीक्षण या जांच ऐसे

व्यक्ति या व्यक्तियों, जैसा यह निदेश दें, द्वारा करवाने और क्लिनिकल स्थापन से संबद्ध किसी अन्य विषय के बारे में जांच करवाने की शक्ति होगी तथा वह क्लिनिकल स्थापन वहां उस समय प्रतिनिधित्व का हकदार होगा।

(2) प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन संचालित की गई जांच की रिपोर्ट क्लिनिकल स्थापन को संसूचित करेगा और क्लिनिकल स्थापन के दृष्टिकोण को अभिनिश्चित करने के पश्चात्, क्लिनिकल स्थापन को की जाने वाली कार्रवाई पर परामर्श दे सकेगा।

(3) क्लिनिकल स्थापन किसी कार्रवाई, यदि कोई है, जो ऐसे निरीक्षण या जांच रिपोर्ट पर की जानी प्रस्तावित है या की गई है, की रिपोर्ट प्राधिकारी को देगा।

(4) जब क्लिनिकल स्थापन, युक्तियुक्त समय के भीतर, प्राधिकारी के समाधानप्रद कार्रवाई नहीं करता है, तो वह क्लिनिकल स्थापन द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश, जैसे वह उचित समझे, जारी करेगा और क्लिनिकल स्थापन ऐसे निदेशों की अनुपालना करने के लिए आबद्ध होगा।

17. प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, यदि कोई संदेह है कि कोई क्लिनिकल स्थापन को बिना रजिस्ट्रीकरण के चला रहा है, तो वह युक्तियुक्त समय पर ऐसे क्लिनिकल स्थापन में विहित रीति में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और क्लिनिकल स्थापन निरीक्षण या जांच के लिए युक्तियुक्त प्रसुविधाएं प्रदान करेगा तथा वहां पर प्रतिनिधित्व का हकदार होगा और प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

संदेहयुक्त  
रजिस्ट्रीकृत  
क्लिनिकल  
स्थापन का  
निरीक्षण।

18. प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध समस्त अपीलें राज्य रजिस्ट्रार को की जाएंगी।

19. (1) प्राधिकारी, उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत क्लिनिकल स्थापनों का रजिस्टर डिजिटल फारमेट में अनुरक्षित रखेगा और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टर में प्रमाणपत्र की विशिष्टियों की प्रविष्टि करेगा।

क्लिनिकल  
स्थापन का  
रजिस्टर।

(2) प्रत्येक प्राधिकारी, क्लिनिकल स्थापनों के राज्य रजिस्ट्रार को, रजिस्टर में डिजिटल फारमेट में की गई प्रत्येक प्रविष्टि की एक प्रति, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए भेजेगा कि राज्य रजिस्टर, राज्य में प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षित किए गए रजिस्ट्रारों के साथ निरन्तर अद्यतन है ।

क्लिनिकल  
स्थापन के  
राज्य  
रजिस्टर का  
अनुरक्षण ।

20. राज्य रजिस्ट्रार क्लिनिकल स्थापनों के रजिस्टर के नाम से ज्ञात रजिस्टर को डिजिटल फारमेट में ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अनुरक्षित रखेगा ।

अरजिस्ट्रीकरण  
से सम्बन्धित  
अपराध ।

21. (1) जो कोई भी क्लिनिकल स्थापन को बिना रजिस्ट्रीकरण से चलाता है, दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध के लिए, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, द्वितीय अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और किसी भी पश्चात्पूर्ति अपराध के लिए, रजिस्ट्रीकरण हेतु स्थाई रुप से निरर्हताग्रस्त होने सहित जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, किन्तु किसी भी मामले(दशा) में जुर्माना पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई ऐसे क्लिनिकल स्थापन में जानबूझकर सेवा करता है, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, अपराध का दोषी होगा और जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा किन्तु पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा ।

आदेश की  
अवज्ञा, बाधा  
डालना और  
सूचना देने  
से इन्कार  
करना ।

22. (1) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्ण दिए गए किसी निदेश की जानबूझकर अवज्ञा करता है या किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के किन्हीं कृत्यों के निर्वहन, जिनके लिए ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित या सशक्त है, में बाधा डालता है, तो वह जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा किन्तु पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई, जिससे इस अधिनियम द्वारा या के अधीन कोई सूचना देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी सूचना जानबूझकर रोकता है या ऐसी सूचना देता है जिसे वह जानता है कि यह मिथ्या है या उसे विश्वास है कि यह सत्य नहीं है, तो वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, किन्तु बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा ।

23. (1) जो कोई इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या जारी अधिसूचना के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी कमियां होती हैं जिनसे किसी रोगी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कोई आसन्न खतरा उत्पन्न नहीं होता है और जिसे युक्तियुक्त समय में सुधारा जा सकता है, तो वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, किन्तु बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा ।

(2) इस धारा के अधीन समस्त अपराध शमनीय होंगे और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार उन पर संक्षिप्त विचारण किया जाएगा ।

24. जो कोई, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या जारी अधिसूचना के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, यदि अपराध के लिए कोई जुर्माना उपबन्धित नहीं है, तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, द्वितीय अपराध के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, किन्तु किसी भी मामले (दशा) में पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा, दायी होगा ।

25. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके लिए उत्तरदायी था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का दायी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध जब किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो जाए कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य

अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा ।

**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के प्रयोजन के लिए “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म, सोसाइटी, न्यास और व्यक्तियों के संगम, चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित हैं ।

सदभावपूर्वक की गई कार्यवाई के लिए संरक्षण ।

**26.** इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या किसी प्राधिकारी या परिषद् के किसी सदस्य या इस निमित्त प्राधिकृत इनके अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं होगी ।

अपराध का संज्ञान ।

**27.** कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान साधारणतः या विशेष आदेश द्वारा परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी या परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किए गए लिखित परिवाद के सिवाए नहीं करेगा ।

विवरणियां देना ।

**28.** (1) प्रत्येक क्लिनिकल स्थापन, ऐसे समय के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर जैसा इस निमित्त विहित किया जाए, प्राधिकारी या परिषद् या राज्य सरकार को ऐसी विवरणियां, आंकड़े और अन्य सूचना, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, देगा ।

(2) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी की क्लिनिकल स्थापन की उचित कार्यप्रणाली के लिए विवरणियां, आंकड़े और अन्य सूचना देने सहित निदेश जारी करने की शक्ति होगी जोकि बाध्यकारी होगी ।

प्राधिकारी, आदि का लोक सेवक होना ।

**29.** इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला या प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक प्राधिकारी, परिषद्, इसके अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

30. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के नियम पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थातः—

- (क) धारा 8 के अधीन परिषद् का गठन ;
- (ख) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन परिषद् के सदस्यों के भत्ते ;
- (ग) रीति , जिसमें सूचना प्रदर्शित की जानी है ;
- (घ) धारा 10 और 14 के अधीन किए गए आवेदनों का प्ररूप ;
- (ङ) धारा 10 की उपधारा (4) और 14 की उपधारा (7) के अधीन जारी किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप ;
- (च) रजिस्ट्रीकरण की शर्तें ;
- (छ) धारा 4 और 5 के अधीन प्रसुविधाओं, सेवाओं आदि के लिए न्यूनतम मानक ;
- (ज) लोक सूचना के लिए क्लिनिकल स्थापनों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली सूचना ;
- (झ) धारा 14, 15 तथा 16 के अधीन क्लिनिकल स्थापन के निरीक्षण हेतु प्रक्रिया ;
- (ञ) धारा 5 के अधीन क्लिनिकल स्थापन का वर्गीकरण ; और
- (ट) कोई अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो, या पूर्वोक्त क्रमवर्ती सत्रों के अवसान से पूर्व

विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे उपान्तरण या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाईयों  
को दूर  
करने  
की शक्ति ।

31. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।



# THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE CLINICAL ESTABLISHMENTS REGISTRATION AND REGULATION BILL, 2007

## ARRANGEMENT OF CLAUSES

### *Clauses :*

1. Short title.
2. Definitions.
3. Registration.
4. Essential conditions.
5. Classification.
6. Clinical Establishment Registration Authority.
7. State Registrar.
8. State Clinical Establishment Council.
9. Sources of revenue.
10. Application for registration.
11. No inquiry prior to provisional registration.
12. Renewal of registration.
13. Permanent registration.
14. Application for permanent registration.
15. Revocation of registration.
16. Inspection of registered Clinical Establishments.
17. Inspection of suspected unregistered Clinical Establishments.
18. Appeals.
19. Register of Clinical Establishment.
20. Maintenance of State Register of Clinical Establishments.
21. Offences relating to non-registration.
22. Disobedience of order, obstruction and refusal of information.
23. Deficiencies minor in nature.
24. General provisions
25. Offences by companies.
26. Protection of action taken in good faith.
27. Cognizance of offence.
28. Furnishing of returns.
29. Authority etc. to be public servant.
30. Power to make rules.
31. Power to remove difficulties.

**THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE CLINICAL  
ESTABLISHMENTS REGISTRATION AND  
REGULATION BILL, 2007**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to provide for the registration and regulation of private Clinical Establishments in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.*

WHEREAS, it is considered expedient and in the public interest to enact a comprehensive legislative framework for the registration and regulation of private Clinical Establishments in the State of Himachal Pradesh;

AND WHEREAS, it is considered expedient to prescribe among others, minimum standards for facilities and services provided with a view to standardizing health care services and for achieving improvement of public health as enjoined by article 47 of the Constitution of India.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows: -

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Private Clinical Establishments Registration and Regulation Act, 2007.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Authority” means the registering authority notified under sub section(1) of section 6;
- (b) “Certificate” means the certificate of registration issued under sub-section(4) of section 10 or sub-section (7) of section 14;
- (c) “Clinical Establishment” means and includes a hospital, maternity home, nursing home, dispensary, clinic,

sanatorium or an institution by whatever name called which offers services, facilities with or without beds requiring diagnosis, treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy and also includes a mobile unit providing the said services, established and administered or maintained by any person or body of persons, whether incorporated or not, but does not include a Clinical Establishment established and administered or maintained by the State Government or the Central Government or a Local Authority;

- (d) "Council" means the State Clinical Establishment Council constituted under section 8 of this Act;
- (e) "notification" means a notification published in the Official Gazette;
- (f) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;
- (g) "practitioner" means a person who is engaged in practice of modern scientific system of medicine and all its branches and has qualification as prescribed in the First, Second or Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956;
- (h) "medicine" shall have the meaning as defined under clause (f) of section 2 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003;
- (i) "standards" mean the conditions as may be prescribed under section 5 of this Act;
- (j) "State" means the State of Himachal Pradesh;
- (k) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;
- (l) "regulations" means regulations made by the Council under this Act;
- (m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; and

- (n) "Register" or "State Register" means a register maintained under this Act and the expression 'registered' and 'registration' shall be construed accordingly.

Registration.

3. (1) No practitioner shall carry on a Clinical Establishment unless it has been registered in accordance with the provisions of this Act.

(2) No person shall be employed by or associated with any Clinical Establishment unless he possess relevant recognized medical qualification under any State or Central Act.

*Explanation.*— The expression 'carry on' means to receive patients in a Clinical Establishment for providing treatment, diagnosis or nursing care.

Essential  
conditions.

4. Every Clinical Establishment shall fulfil for registration and thereafter, such conditions as the State Government may prescribe which may include standards for facilities and services, qualifications of personnel, maintenance of records, and incident reporting.

Classification.

5. Clinical Establishments shall be classified into such categories as may be prescribed by the State Government from time to time and different standards may be prescribed for different categories of Clinical Establishment.

Clinical  
Establish-  
ment Regis-  
tration  
Authority

6. (1) The Deputy Commissioner or Additional Deputy Commissioner of the District, as may be notified by the State Government, for each District, shall be the Authority for the purposes of grant of permission for registration of Clinical Establishment within their respective jurisdiction under this Act excluding mobile units.

(2) The Chief Medical Officer of the District shall be the District Registrar of Clinical Establishments.

(3) It shall be the responsibility of the District Registrar to send such returns as may be prescribed for regular updating of the State Register of Clinical Establishments and such other information as may be required by the Council.

7 (1) The State Government shall designate Director Health Services, Himachal Pradesh as the State Registrar of Clinical Establishments. State Registrar.

(2) All the mobile units registered with any transport authority within or outside the State shall be registered with State Registrar.

(3) It shall be the responsibility of the State Registrar of Clinical Establishments to compile and update the State Register of Clinical Establishments and further to send monthly returns in digital format for updating the State Register.

8. (1) There shall be a State Clinical Establishment Council, for determining standards for Clinical Establishments, to be constituted by the State Government for,— State Clinical Establishment Council.

- (a) the classification of Clinical Establishment;
- (b) developing and determining minimum standards and their periodic review;
- (c) compiling, maintaining and updating a State Register of Clinical Establishments; and
- (d) performing such other function as may be prescribed by the State Government from time to time.

(2) The Council shall consist of the following members, namely:—

- (a) Secretary (Health) to the Government of Himachal Pradesh - Chairman;
- (b) Director Medical Education Himachal Pradesh - Ex-officio member;
- (c) Director Health Services Himachal Pradesh - -do-
- (d) Director (Indian System of Medicine) (Ayurveda) Department Himachal Pradesh - -do-
- (e) Registrar Department of,—

- |       |  |                       |
|-------|--|-----------------------|
| (i)   | Medical Council of Himachal Pradesh;   | - Ex-officio member;  |
| (ii)  | Dental Council of Himachal Pradesh   | - -do-                |
| (iii) | Nursing Council of Himachal Pradesh  | - -do-                |
| (iv)  | Para Medical Council of Himachal Pradesh   | - -do-                |
| (v)   | Pharmacy Council of Himachal Pradesh   | - -do-                |
| (f)   | One representative from amongst the private Hospital Owners  | - Non Official Member |
| (g)   | Not more than three eminent representatives of - -do- other recognized systems of medicine, of which no statutory regulatory authority has been set up to be nominated by the State Government |                       |
| (h)   | One representative from State level Consumer - -do- groups or Non Government Organizations, to be nominated by the State Government.   |                       |

(3) The nominated members of the Council shall hold office for a term of one year but shall be eligible for re-nomination:

Provided that the nominated member shall hold office for so long as he holds the appointment of the office by virtue of which he was nominated to the Council.

(4) The Nominated members of the Council shall be entitled to travelling allowance and daily allowance for effective sitting of the Council at such rate as may be prescribed.

(5) The Council may, subject to the previous approval of the State Government, prescribe its own procedure for the conduct of all business to be transacted by it including fixing of quorum.

(6) The Council may constitute sub-committees and may appoint to such sub-committees, for the period not exceeding two years, on temporary

basis, for the consideration of any particular matter, persons who are not members of the Council.

(7) The Council may perform its functions notwithstanding any vacancy therein.

(8) The State Government shall appoint a person to be the Secretary of the Council and may provide the Council with such other staff, as the Council may consider necessary.

(9) The Council may associate with itself any person or body whose assistance or advice it may require in carrying out any of the provisions of this Act, on such terms and conditions as may be prescribed.

(10) The Council may follow a consultative process for determining standards and for classification of Clinical Establishments in accordance with the procedure to be prescribed by the Council by regulations.

9. The Council may charge such fee from the Authority, for the maintenance of of the State Register, as may be prescribed by regulations:

Sources of revenue.

Provided that such fee shall not exceed 2 % of the total fees charged by the Authority from the Clinical Establishments for registration and renewal thereof.

10. (1) For the purpose of registration of the Clinical Establishment, an application shall be made to the Authority in such form containing such details and such fee as may be prescribed.

Application for registration.

(2) The Authority shall facilitate online submission of applications so as to minimize the interface between the Authority and the applicant.

(3) Any Clinical Establishment, whether registered, or not, in existence on the date of commencement of this Act, shall make an application to the Authority for its registration, within three months from the date of commencement of this Act.

(4) The Authority shall, within a period of ten days from the date of receipt of such application; grant a Certificate of provisional registration in

such form containing such particulars and such information as may be prescribed.

(5) The provisional registration Certificate granted under sub-section (4) shall be valid for one year from the date of registration and shall be renewable on yearly basis for maximum period of three years.

(6) The Certificate of registration shall be kept affixed in a conspicuous place in the Clinical Establishment in such a manner so as to be visible to every one visiting such Establishment.

(7) In case the Certificate is lost, destroyed, mutilated or damaged, the Authority shall issue a duplicate Certificate on the request of the Clinical Establishment and on the payment of such fee as may be prescribed.

(8) The Certificate of registration shall be non-transferable and in the event of change of ownership or change of management or on ceasing to function as a Clinical Establishment, the Certificate of registration shall be surrendered to the Authority and the Clinical Establishment shall apply afresh for grant of Certificate of registration.

No Enquiry  
prior to  
provisional  
registration.

11. (1) The Authority shall not be required to conduct any enquiry prior to the grant of Certificate of provisional registration.

(2) Notwithstanding the grant of the provisional Certificate of registration, the Authority shall, within a period of forty-five days from the grant of provisional Certificate of registration, cause to be published in such manner as may be prescribed, all particulars of the Clinical Establishment proposed to be registered.

Renewal  
of  
registration.

12. (1) The Authority shall cause to be published, in such manner as may be prescribed, the names of Clinical Establishments whose registration would be expiring within the next forty-five days.

(2) The Authority shall cause to be sent, either electronically or by post, to every Clinical Establishment a computer generated notice, forty-five days prior to the expiry of the registration.



(3) Application for renewal of registration shall be made well before the expiry of the validity of the Certificate of provisional registration and if the application for renewal is made after the expiry of the provisional registration, the Authority shall allow renewal of registration on payment of such late fee as may be prescribed.

13. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 10, permanent registration shall be granted only after the State Government has prescribed minimum standards for the registration of Clinical Establishments, as determined by the Council. Permanent registration.

(2) The Clinical Establishments in respect of which minimum standards have been prescribed, provisional registration shall not be granted or renewed beyond a period of twelve months from the date of notification of standards.

14. (1) Application for permanent registration shall be made to the Authority in such form and in such manner and containing such details and such fees as may be prescribed. Application for permanent registration.

(2) The Authority shall cause to be published, in such manner as may be prescribed, all such information/ details submitted under sub-section (1), for a period of thirty days, before grant of permanent registration, for information of the general public.

(3) The District Registrar shall cause an inspection of the Clinical Establishment as to the prescribed minimum standards and convey the same to the Authority concerned.

(4) If no objection(s) is received by the Authority, within thirty days from the date of publication, or the report of the District Registrar is satisfactory as to the prescribed minimum standards, permanent registration shall be granted.

(5) If any objection(s) is received within the stipulated period or the report of the District Registrar is not satisfactory, the objection(s) so received shall be communicated to the applicant within such period as may be prescribed but not later than 30 days.

(6) Immediately after the expiry of the stipulated period and within the next thirty days thereafter, the Authority shall by order,—

- (a) allow the application for permanent registration; or
- (b) disallow the application for permanent registration.

(7) If the application is allowed, the Authority shall issue a Certificate of permanent registration in such form and containing such particulars as may be prescribed.

(8) If the application for permanent registration is not allowed the Authority shall clearly state the reasons thereof:

Provided that a Clinical Establishment shall not be debarred from making a fresh application for permanent registration, even if its earlier application has been disallowed, after having rectified the deficiencies on which grounds the earlier application was disallowed.

Revocation  
of  
registration.

15. (1) If at any time, after a Clinical Establishment has been registered, the Authority is satisfied that,—

- (a) the conditions of the registration are not being complied with; or
- (b) any of the grounds that would have entitled the Authority to reject the application for registration was suppressed at the time of the application; or
- (c) the person entrusted with the management of the Clinical Establishment has been convicted of an offence punishable under this Act;

it may issue a show cause notice as to why its registration under this Act should not be cancelled for the reasons mentioned in the notice. If after giving a reasonable opportunity of being heard to the Clinical Establishment, the Authority is satisfied that there has been a breach of any of the provisions of this Act or the rules made there under, it may, without prejudice to any other

action that it may take against such Clinical Establishment, cancel its registration.

(2) Every order made under sub-section (1) shall take effect,—

- (a) where no appeal has been preferred against such order, immediately on the expiry of the period prescribed for such appeal; or
- (b) where appeal has been preferred and it has been dismissed, from the date of the order of such dismissal:

Provided that the Authority, after cancellation of registration for reasons to be recorded in writing, may restrain the Clinical Establishment from carrying on any of its function if there is imminent danger to the health and safety of patients.

16. (1) The Authority or an officer authorized by it, shall have the power to cause an inspection of, or inquiry in respect of any Clinical Establishment, its buildings, laboratories and equipments and also of the work conducted or done by the Clinical Establishment, to be made by such person or persons as it may direct and to cause an inquiry to be made in respect of any other matter connected with the Clinical Establishment and that Clinical Establishment shall be entitled to be represented there at.

Inspection  
of registered  
clinical  
establish-  
ment.

(2) The Authority shall communicate to the Clinical Establishment report of the inquiry conducted under sub-section (1) and after ascertaining the views of the Clinical Establishment, may advise the Clinical Establishment upon the action to be taken.

(3) The Clinical Establishment shall report to the Authority the action, if any, which is proposed to be taken or has been taken upon the report of such inspection or inquiry.

(4) Where the Clinical Establishment does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Authority, it may, after considering any explanation furnished or representation made by the Clinical Establishment, issue such directions as it deems fit and the Clinical Establishment shall be bound to comply with such directions.

- Inspection of suspected unregistered clinical establishment. **17.** The Authority or an officer authorized by it may, if there is any reason to suspect that anyone is carrying on a Clinical Establishment without registration, enter and search in the manner prescribed, at any reasonable time, such Clinical Establishment and the Clinical Establishment shall offer reasonable facilities for inspection or inquiry and shall be entitled to be represented thereat, and the Authority shall recommend action to be taken under this Act.
- Appeals. **18.** All appeals against the orders of the Authority shall lie to the State Registrar.
- Register of Clinical Establishment. **19.** (1) The Authority shall maintain in digital format a Register of Clinical Establishments, registered by it and shall enter the particulars of the Certificate in a Register to be maintained in such form and in such manner as may be prescribed.
- (2) Each Authority shall supply in digital format to the State Registrar of Clinical Establishments a copy of every entry made in the Register in such manner as may be prescribed to ensure that the State Register is constantly up to date with the Registers maintained by the Authorities in the State.
- Maintenance of State Register of Clinical Establishment. **20.** The State Registrar shall maintain in digital format a Register to be known as the State Register of Clinical Establishments in such form and in such manner as may be prescribed.
- Offences relating to non-registration. **21.** (1) Whoever carries on a Clinical Establishment without registration shall, on conviction, for first offence be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees, for second offence with fine which may extend to two lakhs rupees and for any subsequent offence with fine which may extend to five lakhs rupees with permanent disqualification for registration, but in any case fine shall not be less than twenty five thousand rupees.
- (2) Any person, who knowingly serves in a Clinical Establishment, which is not registered under this Act, shall be guilty of an offence and shall be punishable with fine, which may extend to twenty five thousand rupees but shall not be less than five thousand rupees.

22. (1) Whoever, wilfully disobeys any direction lawfully given by any person or authority empowered under this Act, or obstructs any person or authority in the discharge of any functions which such person or authority is required or empowered under this Act, shall be punishable with fine which may extend to five lakhs rupees but shall not be less than fifty thousand rupees.

Disobedience of order, obstruction and refusal of information.

(2) Whoever required by or under this Act, to supply any information, wilfully withholds such information or gives information which he knows to be false or which he does not believe to be true, shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees but shall not be less than twenty thousand rupees.

23. (1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act or any rule, regulation or notification made thereunder, resulting in deficiencies that do not pose any imminent danger to the health and safety of any patient and can be rectified within a reasonable time, shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees but shall not be less than ten thousand rupees.

Deficiencies minor in nature.

(2) All offences under this section shall be compoundable and shall be tried summarily in accordance with the procedure provided for summary trials in the Code of Criminal Procedure, 1973.

24. Whoever contravenes any of the provisions of this Act, rule, regulation or notification made thereunder, shall, if no fine is provided for the offence, be liable to fine for first offence which may extend to ten thousand rupees, for the second offence with fine which may extend to fifty thousand rupees and for subsequent offence with fine which may extend to five lakhs rupees but in any case fine shall not be less than five thousand rupees.

General provision.

25. (1) Where any offence punishable under this Act, has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in-charge of, and was responsible to the company for the conduct of its business, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Offences by companies.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was

committed without his knowledge and that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence punishable under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or; other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

*Explanation.*—For the purpose of this section, “company” means a body corporate and includes a firm, society, trust or other association of individuals whether incorporated or not.

Protection  
of action  
taken in  
good faith.

**26.** No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government or any Authority or any member of the Council or their officers and employees authorized in this behalf, in respect of anything, which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or any rules or regulations made thereunder.

Cognizance  
of offence

**27.** No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act, except upon a complaint in writing, made by the Authority or any other officer authorized by the Council in this behalf by a general or special order.

Furnishing  
of returns.

**28. (1)** Every Clinical Establishment shall, within such time or within such extended time as may be prescribed in this behalf, furnish to the Authority or Council or the State Government such returns, statistics and other information in such manner as may be prescribed.

(2) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, Authority shall have the power to issue directions including furnishing of returns, statistics and other information for the proper functioning of Clinical Establishments which shall be binding.

Authority  
etc. to be  
public  
servant.

**29.** Every Authority, Council its officers and employees, exercising or authorized to exercise powers under this Act or the rules made thereunder shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

**30.** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette and after previous publication make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters namely:—

- (a) Constitution of the Council under section 8;
- (b) Allowances of the members of the Council under sub-section (4) of section 8;
- (c) The manner in which to display the information;
- (d) The form of the applications to be made under sections 10 and 14;
- (e) The form of the Certificate of registration to be issued under sub-section (4) of section 10 and sub-section (7) of section 14;
- (f) The conditions of registration;
- (g) The minimum standards for facilities, services etc. under sections 4 and 5;
- (h) The information to be displayed by the Clinical Establishment for public information;
- (i) The procedure for inspection of Clinical Establishment under sections 14, 15 and 16;
- (j) Classification of Clinical Establishment under section 5; and
- (k) Any other matter which is required to be or may be prescribed by the State Government.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive session, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive session aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that the rules should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to  
remove  
difficulties.

31. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provision of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before State Legislative Assembly.